

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, Shri Madhu Limaye and Shri George Fernandes had given notice of a privilege motion. Is that privilege motion still under your consideration ?

MR. SPEAKER : On what subject ?

SHRI S. M. BANERJEE : On Rs. 10,000 taken by Shri Nijalingappa and Rs. 5,000 by Shri Patil. They have issued a statement distorting parliamentary proceedings.

MR. SPEAKER : I will look into it.

12.51 hrs.

CRIMINAL AND ELECTION LAWS
(AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. SPEAKER : The House will now take up further clause-by-clause consideration of the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898, and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters, as reported by the Joint Committee.

The time allotted by the Business Advisory Committee for this Bill was three hours and the time already taken is four hours. I think, it is a very unhealthy practice that when the Business Advisory Committee fixes the time and the whole House approves of it, we still exceed that limit. That is not good because the extra time is taken out of the time to be given to other motions. I hope, the House will look into it.

Now let us see that this Bill is passed without taking much time. How much time more should we have for this 15 minutes or half an hour ?

SHRI SHRI CHAND GOYAL
(Chandigarh) : One hour more.

MR. SPEAKER : But this is the first and the last time that I will depart from the report of the Business Advisory Committee because it has already been done. In future unless I make a reference to the Business Advisory Committee again, on my own I will have no right to extend the time when the Business Advisory Committee has recommended and the House has approved it.

श्री जार्ज फर्नेन्डिस (बम्बई-दलिया) : एक घंटा बढ़ाने का आप को अधिकार है। आप अपने इस अधिकार को न छोड़िये।

MR. SPEAKER : I wish we could sit throughout the year ; but we have some other things to do also.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : We do not want you to abdicate your right. You have the right to extend the time.

MR. SPEAKER : I do not want to exercise it. Please do not give me too many rights,

Clause 3—(Amendment of section 505)

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon) : Sir, I move :

Page 2, lines 34 and 35,—

after "ceremoniest" insert—

"or in educational, social and religious institutions or in Government offices where Unions function" (4)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : Sir, I move :

Page 2, lines 26 and 27,—

omit "or any other ground whatsoever" (15)

Page 2, lines 34 and 35,—

after "ceremonies," insert—

"in respect of any election or otherwise" (16)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I move :

Page 2, line 25,—

after "promote," insert "only" (29)

श्री प्रबुल गनी डार : मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि काश्मीर में जब इलेक्शन हो रहे थे तब इलेक्शन कमिश्नर ने पार्टी पालिटिक्स में दखल देने की कोशिश की थी और ऐसा करके और इस तरह का रोल अदा करके अपने आप को धोखा दिया था और अपने आपको उसमें उलझाया था। मैं चाहता हूँ कि जब कभी गवर्नमेंट कोई बिल लाये तो उसमें ऐसी कर्तव्य भी

بھ رہے تاکہ इलॅक्शन कमिशनर चाहे कोई भी हों, ए० हों या बी० हो, किसी पार्टी का रिप्रिजेंटेटिव न बन सके और इलॅक्शन में इस तरह के व्हाल न दे सके। कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमायत थी। हम समझते हैं कि उसमें राय का इजहार करने की आजादी है। उसमें भाज बगावत भी हो रही है। इलॅक्शन कमिशनर को क्या मतलब कि कौनसी पार्टी घाती है या कौनसी नहीं घाती है। मैं चाहता हूँ कि इस क्लॉज को भाप इस तरह से ढालें जिससे यह बात क्लीयर हो जाये --

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इनकी प्रमेंडमेंट कौन सी है, यह तो जरा बतायें।

अध्यक्ष महोदय : वह सक्नुंलेट हो गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इनको मालूम ही नहीं है कि इनकी एमेंडमेंट क्या है।

श्री अश्वदुल गनी डार : न मिर्फ रिलिजन और लेंगुएज बल्कि जिस किसी दूसरी जगह से भी घ्रापस में तान्लुकात बिगड़ते हों, फिर चाहे जगजीवन राम जी और निजलिगप्पा के दरम्यान बिगड़ते हों या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के दरम्यान बिगड़ते हों या हिन्दुओं और मुसलमानों के दरम्यान बिगड़ते हों या हरिजनों और सिखों के दरम्यान बिगड़ते हों, उसको इजाजत नहीं होनी चाहिये। यह क्लीयर किया जाना चाहिये कि अफसरों को भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमिशनर को भी कोई हक नहीं है कि वह किसी एक सास पार्टी को कामयाब कराने की कोशिश करे।

श्री अश्वदुल गनी डार : मैंने पहली बार इसी मुद्दे का कन्सिडरेशन किया था कि क्या कन्सिडरेशन में अफसरों को भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमिशनर को भी कोई हक नहीं है कि वह किसी एक सास पार्टी को कामयाब कराने की कोशिश करे।

श्री अश्वदुल गनी डार : मैंने पहली बार इसी मुद्दे का कन्सिडरेशन किया था कि क्या कन्सिडरेशन में अफसरों को भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमिशनर को भी कोई हक नहीं है कि वह किसी एक सास पार्टी को कामयाब कराने की कोशिश करे।

श्री अश्वदुल गनी डार : मैंने पहली बार इसी मुद्दे का कन्सिडरेशन किया था कि क्या कन्सिडरेशन में अफसरों को भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमिशनर को भी कोई हक नहीं है कि वह किसी एक सास पार्टी को कामयाब कराने की कोशिश करे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इनकी एमेंडमेंट कौन सी है, यह तो जरा बतायें।

अध्यक्ष महोदय : वह सक्नुंलेट हो गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इनको मालूम ही नहीं है कि इनकी एमेंडमेंट क्या है।

श्री अश्वदुल गनी डार : मैंने पहली बार इसी मुद्दे का कन्सिडरेशन किया था कि क्या कन्सिडरेशन में अफसरों को भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमिशनर को भी कोई हक नहीं है कि वह किसी एक सास पार्टी को कामयाब कराने की कोशिश करे।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cutback) : Sir, I moved a similar amendment earlier also I want to put one example before the Minister. The Bill seeks to provide that if anybody creates, by some means or other which are described there, enmity between communities, between various religious groups and other things, he will be punished. That will be an offence.

Now, let us take one example. Suppose for a Piece of land, two villagers want to fight. It so happens that one villager belongs to one community and the other villager belongs to another community. Will the Minister bring it under this Bill? The cause is not such; the cause is some land or some tank. I want to suggest that it will be only on the ground of religion, caste, community, etc. I want to add "only" and this will safe guard the interests, rather the civil rights, of the people. They may as well go to litigation; there may be illwill regarding civil liberties and political rights as well. What he intends to prohibit is, between communities there should be no ill feeling; in religion as such there should be no ill feeling. That is what he wants to prohibit. By adding the word "only", this position will be safeguard. That is my contention. I think, the hon. Minister will accept it although he did not accept a similar amendment earlier.

[Shri Srinibas Misra]

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Mr. Speaker, Sir, hon. Member, Shri Abdul Ghani Dar, has moved an amendment seeking to add "or in educational, social and religious institutions or in Government offices where Unions function." We have already debated this particular question at the consideration stage of the Bill. As I have already said, it will not be possible for us to accept this amendment.

As far as Shri Srinibas Misra's amendment is concerned, I would like to point out, the hon. Member also knows that this provision "on any other ground whatsoever" is already existing in the I.P.C.

It is not that we are trying to put it. There is no reason why in this amending Bill we should try to restrict the provisions which we already find in section 505 (2) of the I.P.C. This is not a new thing; this is an old one. What Mr. Srinibas Misra's amendment seeks to do is not to amend the present amending Bill but amend the existing provisions of I.P.C. Therefore, it is not possible for me to accept this.

MR. SPEAKER : The House stands adjourned for Lunch till 2.00 P.M.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

CRIMINAL AND ELECTION LAWS
(AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. CHAIRMAN : We were on Clause 3. I will put all the amendments to Clause 3 to the vote of the House.

Amendments Nos. 4, 15, 16 and 29 were put and negatived

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill

Clause 4—(Amendment of Act 5 of 1898)

MR. CHAIRMAN : Now, we go to Clause 4. Shri Shiv Chandra Jha.

SHRI SHIV CHANDRA JHA (Madhubani) : I move all the three amendments.

I move :

Page 3, line 11,—

for "classes" substitute "communities"
(17)

Page 3, line 20,—

for "classes" substitute "communities"
(18)

Page 3, line 53,—

for "classes" substitute "communities"
(19)

सभापति जी, मेरे संशोधन का नम्बर 17, 18 और 19 है। उसमें मैंने यह कहा है कि पेज 3 पर जहाँ कहीं भी क्लामेज शब्द आया है उस की जगह पर कम्युनिटी शब्द रख दिया जाय। यह तीन जगह पर है। इसकी वजह यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य जो है कम्युनल तफरके, या साम्प्रदायिक झगड़े, दंगा फिसाद, फिरका-परस्ती इन सब चीजों को खत्म करना है। क्लामेज के बीच में जो संघर्ष है उसको खत्म करने का मतलब है सरकार का तो हम साफ कहना चाहते हैं कि हम उसमें विश्वास करते हैं। हम क्लामेज हारमोनी में विश्वास नहीं करते। हम क्लामेज एनिमिटी में विश्वास करते हैं, क्लामेज स्ट्रिगल में विश्वास करते हैं। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। मानव समाज का लिखित इतिहास शुरू से लेकर आज तक इस क्लामेज स्ट्रिगल

की बदौलत आगे बढ़ा है और अभी भी हिन्दुस्तान में क्लास स्ट्रगिल से काम हो रहा है। जो कुछ भी अच्छे कदम उठाए जाते हैं, आम जनता के लिए वह क्लास स्ट्रगिल की बदौलत ही उठाए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है यह अपनी तरफ से नहीं किया है, हिन्दुस्तान के समाज में हम लोगों ने जो आवाजें उठाईं, हिन्दुस्तान के मजदूर आन्दोलन ने आवाज उठाई, यहां के भवाम ने आवाज उठाई कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो तब जा कर यह कदम उठाया गया। इसी तरह से और भी जो काम होंगे समाज की भलाई के लिये, हिन्दुस्तान के समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाजवाद की मंजिल पर ले जाने के लिए उसमें क्लास स्ट्रगिल का प्रथम हाथ होगा। इसीलिए यदि सरकार चाहती है क्लास स्ट्रगिल को, क्लासेज के बीच में जो एनिमिटी है उसको खत्म किया जाय तो हम साफ कहना चाहते हैं कि हम उस स्ट्रगिल को खत्म नहीं करना करना चाहते, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। जो विधेयक है उसमें शुरू से आखीर तक मैंने पढ़ा कहीं यह शब्द क्लासेज नहीं है, यह शब्द सिर्फ यहीं पर है जिसके लिए यह संशोधन मैंने दिये हैं। बाकी सब जगह कम्युनिटी लपज ठीक रखा है। लेकिन यहां पर क्लासेज शब्द कैसे आ गया यह मैं समझ नहीं सका। मैं समझता था कि यह शायद प्रिटिंग मिस्टेक हो, इन लोगों ने गौर नहीं किया। इसी लिए मैंने यह संशोधन दिया है। मैं क्लासेज शब्द को हटाना चाहता हूँ और उसकी जगह कम्युनिटी को रखना चाहता हूँ। मैं कम्युनिटीज में जो भगड़े होते हैं उनको खत्म करना चाहता हूँ। इसमें हम सब विश्वास करते हैं कि साम्प्रदायिक भगड़े और फिरकापरस्ती को खत्म किया जाय। इसी की बदौलत हिन्दुस्तान का बंटबारा हुआ। इसकी हम लोग वह कीमत चुका चुके हैं कि भारत को अपनी आँखों बंटते देख चुके।

फिरकापरस्ती का जो बहुर फैला है,

वेस्टेड इन्टरेस्ट्स और मुनाफाखोरो की बदौलत, जो लोग यह चाहते हैं कि ये भावनायें बढ़ें और क्लास स्ट्रगिल की भावनायें बढ़ें नहीं ताकि उनकी जो दुनिया आबाद है, सदा ही जो वे बसन्त का मौसम अनुभव करते हैं, उनका वह मौसम और उनको वह दुनिया समाप्त न होने पाये; इसलिये मैं चाहूँगा कि जो आपका आदर्श है जिस आदर्श को आपने सामने रखा है उसमें थोड़ा बहुत मतलब भी आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत उपयुक्त होगा कि क्लास शब्द को हटा दें और उसके स्थान पर कम्युनिटी शब्द रखें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The hon. Member has sought to bring many more things in these words than are intended here in this Bill. It is simply a legal terminology that is being used to clearly indicate what the wish of the legislature is in enacting this. There is no question of class struggle or non-class struggle or community struggle and all those high-sounding words that he has used. This is a simple legislation in which we want to provide that anybody who creates any dissensions or difficulties which lead to communal disturbances or other kinds of disturbances in the country which lead to violence has to be prevented from doing so. That is why we have used these words. Substitution of other words in their place would create difficulties as far as the enforcement of this law is concerned. If that is the intention of the hon. Member then I have nothing to say. But our standpoint is this that this particular word that we have used would more appropriate as far as the legal drafting goes, and, therefore, I am unable to accept these amendments.

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendments Nos. 17, 18 and 19 to the vote of the House.

Amendments Nos. 17 to 19 were put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 -- (Power to control prejudicial publications)

SHRI SHIVA CHANDERA JHA : I beg to move :

Page 4, line 29, after 'may' insert "after intimating the Press Consultative Committee" (20)

Page 4, line 36, for 'two months' substitute "one month". (21)

Page 5, line 4, after "order" insert "within a month from the last day of such representation". (22)

SHRI SRINIBAS MISRA : I beg to move :

Pages 4 and 5, for lines 37 to 44 and 1 to 4, respectively substitute :

"Provided further that the authority making the order shall without delay, refer the matter to a Committee to be known as Press Consultative Committee, and modify, confirm or rescind the order after obtaining the opinion of the said Committee." (30)

SHRI P. VISWAMBHARAN : (Trivandrum) : I beg to move :

Page 4, for lines 25 and 26 substitute —

"6 (1) The Central Government in case of Union territories or the concerned State Government in case of States, if". (32)

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I beg to move :

Page 4, line 36, for "two months" substitute "a week" (33)

Page 4, line 38, for "ten days" substitute "three days". (34)

Page 5, lines 11 to 14, omit "and that any printing press or other instrument or apparatus used in the publication be closed down for the period such order is in operation." (35)

MR. CHAIRMAN : These amendments are now before the House.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : I have moved three amendments to

clause 6. My object in moving these amendments is this. This measure is going to act in a very harsh manner on the owners of the printing presses because we are here making a provision that the printing presses can be closed for two months consecutively, which will mean that the press comes to a standstill for two months ; in that cases the small presses especially, which not only perform the job of printing a particular paper but sometimes print small papers or weeklies would be closed down and the printing of the small papers or weeklies would also be adversely affected thereby. This involves the interests of so many other people also. The press may be carrying on some other job, apart from printing a particular paper. If the press is closed down, then all that job will also come to a close. It will also result in throwing out of employment all the employees who are working in the printing press.

This measure being a very harsh one, I would suggest that the period of two months should be reduced to one week. After all, why should we keep the order in force for a consecutive period of two months ; this would be good enough. The period of ten days provided for in the second proviso could also be easily reduced to three days.

In my third amendment, I have sought to omit the words :

"and that any printing press or other instrument or apparatus used in the publication be closed down for the period such order is in operation".

I have moved this amendment and also the previous one in order to achieve this objective namely that the period should be as short as possible and it should not adversely affect the interests of the owners as also the people working in the press. I, therefore, plead that these three amendments may be accepted in order to soften the rigour which is sought to be incorporated in the provisions of this Bill.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : According to the provision in the Bill, the responsibility is cast on that person who is punished or the publisher or the person against whom action is being taken to approach the body created for the purpose for opinion, and, thereafter, the authority will act. That I now seek to provide is that it will be the responsibility of the authority

to refer it to the body to be created and get the opinion of that body. Instead of the onus of getting the opinion from the body being cast on the person against whom action is being taken. I want that it should be incumbent upon the authority to refer it to the press body and gets its opinion before taking action.

I hope the hon. Minister will accept the amendment, because it does not change matters. This only means that the authority will send it to the press body and get its opinion instead of the person against whom action is being taken. This kind of thing has been provided for in so many other measures passed by this House. So, I feel that it should be easy for the hon. Minister to accept this amendment. It will not throw any extra burden on the person against whom action is being taken, if the persons has to go, then the question of limitation will come in, he will have to go through the procedures which he may not be able to do and so on. The authority may can easily follow the procedures and have the matter referred to the press body.

श्री शिवचन्द्र भा : सभापति जी, क्लज 6 में मेरे तीन संशोधन नं० 20, 21 और 22 हैं। 20 में मेरा संशोधन है कि क्लज 6 (8) में जहाँ पर है :

"The Central Government or a State Government or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order, may, by order in writing addressed to the printer, publisher or editor, prohibit the printing or publication of any document...

जो छन्द हैं, इसके बाद में जुड़वाना चाहता

है :
"after intimating the press consultative committee".

सभापति जी, फिरकापरस्ती और फरकापरस्ती के जरिये जो हिंसा होती है या जो और खराबियां होती हैं उनको रोकना ही इस विधेयक का मकसद है। दूसरे, फिरकापरस्ती के बाद जो हिंसा होती है प्रकाशन के जरिए, उसको भी

रोकना इस विधेयक का मकसद है। लेकिन ये शायद ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं और इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि जो फ्रीडम आफ दि प्रेस है उस पर किस तरह से ये इनडायरेक्टली घक्का लगाने जा रहे हैं।

अब फ्रीडम आफ दी प्रेस क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। राज्य सभा में यह बात उठी थी और वहाँ मंत्री जी ने कहा कि प्रेस का राष्ट्रीकरण नहीं करने जा रहे हैं। मैंने जब पढ़ा तो मेरा निश्चित मत है कि मंत्री जी को न राष्ट्रीयकरण का ज्ञान है और प्रेस फ्रीडम का ज्ञान है। ऐसे अज्ञानी मंत्री को प्रेस संचालन के लिये बहाल किया जाता है।

प्रेस के माध्यम से जो फिरकापरस्ती की बात आयेगी उसके लिये प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी बनायेंगे जिसमें जर्नलिस्ट्स और एडिटर रहेंगे और उनसे सलाह मशविरा करके घटना पर गौर करेंगे और आगे कदम बढ़ायेंगे। तो प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी आप जब बनाते हैं, प्रेस के जरिये कोई ऐसा प्रकाशन न हो, तो मैं चाहूंगा कि आप या आपकी स्टेट अथोरिटी समझती है कि यह खबर छपी गयी जिससे हिंसा की बात हो सकती है, फिरकापरस्ती बड़ सकती है तो उस खबर की तालाबन्दी करने जा रहें हैं तो क्यों नहीं प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी को वह खबर करते कि देखो फला प्रेस इस तरह का छाप रहा है इसलिये इस खबर को बन्द करने जा रहे हैं। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो हकीकत में प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी जो बनायेंगे उसको इग्नोर करना है और एक तरह से डमी आर्गनाइजेशन वह हो जायेगी और सरकार की वह आर्गनाइजेशन हो जायेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि आफ्टर इन्टीमेटिंग दी प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी कर दिया जाय।

दूसरा संशोधन यह है कि जहाँ पर तालाबन्दी करेंगे प्रेस में

"Provided that no such order shall remain in force for more than two months from the making thereof".

जिस प्रेस में तालाबन्दी करेंगे, उसके प्रकाशन को रोकेंगे, जो महीने से ज्यादा

[श्री शिव चन्द्र भ्वा]

वह आर्डर लागू नहीं होगा। मैं दो महीने की जगह एक महीना इसलिए करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कोई मंथली हो जो कि एक इशू निकल गया और दूसरा अंक एक महीने के बाद निकलेगा। इसलिए एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिये एक ही अंक पर आप रोक लगायें और प्रैस कंसल्टेटिव कमेटी से बात करके मामले को तय कर लें। और एक महीने के अन्दर डेली के बहुत पीस निकल जायेंगे और वीकली के चार निकल जायेंगे। लेकिन अगर एक महीने की मियाद रखते हैं तो उसमें डेली, वीकली और मंथली आ जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह जुल्मी कानून दो महीने की जगह एक महीना ही लागू रहे।

तीसरा संशोधन है कि वह अपील कर सकता है, जब उस पर कोई कार्यवाही होती है, जैसे अखबार है, पब्लिशर है या प्रिन्टर है, वह अपील कर सकता है।

"The Central Government or the State Government, as the case may be, after consultation with a Committee to be known as the Press Consultative Committee dispose of the matter, modifying, confirming or rescinding the order".

कनसल्टेटिव कमेटी की सलाह में यह उस आर्डर को वापस ले लेंगे। तो मैं उसके आखिर में झुड़वाना चाहता हूँ:

"within a month from the last day of such representation".

एक महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये। जिस प्रैस में तालाबन्दी हो जाती है, जो प्रैस बन्द कर दिया जाता है एक महीने के अन्दर उसका निपटारा किया जाय। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो प्रैस फ्रीडम को धक्का लगेगा, और फिरकापरस्ती की तो बात भूलग रही, एक ऐसा खराब कदम उठायेंगे जिस से जनसंघ का जो ढांचा है उस पर भी धक्का लगेगा। इसलिये मैं चाहूँगा

"within a month from the last day of such representation".

एक महीने के अन्दर में तमाम बिवाद निपटारये जायें जिस प्रैस में तालाबन्दी करते हैं और जिस अखबार को रोकते हैं। यही मेरे संशोधन हैं।

SHRI P. VISWAMBHARAN (Trivandrum): This clause empowers the central Government or any authority so authorised by that Government to issue orders prohibiting the printing or publication of any document, not only in the Union Territories but in the States also. At the same time the State Governments are also given those powers. I am at a loss to understand why those two authorities should function simultaneously. Maintenance of law and order is solely a State subject and every State will be interested in maintaining communal harmony and public order. It is only fair that this power is left to the States and the Central Government reserves to itself those powers in the Union Territories. We hear often that there have been many inroads by the Centre into the powers and authorities of the States. We also hear much about the conflict between the State and the Centre in respect of financial matters, in the formation and deployment of central reserve police and industrial security force and all that. In that light I cannot appreciate why the Central Government should reserve those powers; it can normally authorise an officer of the State Government to discharge those functions. Suppose a State Government takes a different view. Then a controversy may arise in this matter. The Attorney General in his evidence before the Joint Committee for this Bill stated, "There may be a conflict between the orders of the Central Government and the State Government." He says that it is legal and it is within the rights of Parliament to pass this enactment. But he also admits the possibility of conflict. My amendment is to restrict those powers of the Central Government in respect of Union Territories and then give those powers to the State Governments to enforce them in the States. I think it is a fair suggestion which the Government would accept.

SHRI ABDUL GHANI DAR: I move:

Page 4, line 36,—

for "two months" substitute "two weeks" (6)

Page 4, line 38, —

for "ten days" substitute "two days" (7)

Page 5, line 4, —

after "order" insert "within one week" (8)

Page 5, line 5, —

after "(2)" insert—

"After final decision by State or Central Government and" (9)

Page 4, line 25, —

after "Central Government" insert—
"in case of Union territories" (37)

सभापति जी, यह मसला जो है यह काफी गम्भीर है। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल इन्टिग्रेसन के फैसलों के मुताबिक जरूरी था कि कुछ अक्रदाम सरकार करे। सरकार उस पर ऐसे कदम उठा रही है जिसमें कम्युनलिज्म को कम से कम जगह न मिल सके और जितना ज्यादा उसको रोका जा सके, रोका जाय।

यह प्रँस के बारे में कहते हैं। मुझे खुशी हुई पिछले दिनों इन्होंने ऐक्शन लिया उसमें 20 वर्द्ध के अखबार थे और चन्द कुछ दूसरे अखबार थे। गालिबन हो सकता है कि तमाम उर्द्ध के अखबार वाले ही ऐसे हों। अगर सारे भी पकड़े जायें तो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि जो भी गलती करता है उसको पकड़ा ही जाना चाहिये। लेकिन अगर उसमें आफिमसं कुछ ज्यादाती करते हैं, और ज्यादाती इसलिये करते हैं, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि ऐडवाइजरी कमेटी बनाते हैं उसका नोमिनेशन करते हैं, वह ऐडोर्टस आप नहीं चुनेंगे, बल्कि सरकार खुद ही मुकर्रर कर देगी और जिसको चाहे उसको बरी कर दे, जिसको चाहे न बरी करे तो भी सरकार ही हुई, दायें हाथ से भी और बायें हाथ से भी तो एक तो इनको ऐडोर्टस को मौका देना चाहिये।

दूसरा मेरा कहना यह है कि गोयल साहब ने ठीक ही कहा कि दो महीने के लिए क्यों बन्द करने हो? क्योंकि सजा मालिक को तो नहीं मिलती बल्कि दो नौकर हैं उनको मिलती है क्योंकि भ्राम तीर पर ये मालिक बड़े होशियार

होते हैं, डेली बेजेज पर मुलाजिमों को रखते हैं।

डेली बेजेज पर जो काम करते हैं वह बेकार हो जायेंगे। इसलिये अगर ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते रखें तो यह बात उनको शोभा लेगी।

दूसरी भ्रज यह है कि मैंने यह क्यों कहा कि उनको मौका दिया जाय। उन्होंने कहा कि एक महीने में फैसला हो जाय; मैं इसलिये कहता हूँ कि सरकार की नियत बाखैर है। सरकार चाहती है कि वह सही नतीजे पर पहुंचे। लेकिन मेरा जाती तजुर्वा बड़ा तल्ल है। मई, 1947 में मैंने खत लिखे थे और उनको पब्लिश किया था, कायदे प्राजम मरहूम को, नवाब समदोत को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसमें लिखा था कि रावलपिंडी में बहनें और भाई कत्ल हो रहे हैं, उसका नतीजा यह होने वाला है कि बस्ती पंजाब और मशिकी पंजाब में मुसलमानों की डण्डत कोई बचा नहीं सकता। मैंने तो फिरापरस्ती के खिलाफ कहा था और वक्त पर कहा था। मई में लिखा था और मई में वह छप भी गया। फसादात जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए और सितम्बर में खत्म हुए जिनमें करोड़ों आदमी कत्ल हुए और बेकार हुए। मैंने फिरापरस्ती के खिलाफ लिखा था, उल्टे मेरी किताब जन्म कर ली गई। उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मरकार भी मेरी थी और उसने बैसा किया।

इसलिये मेरा कहना है कि अगर आप ऐडवाइजरी कमेटी बनाना चाहते हैं और उनको अधिकार देना चाहते हैं तो वह एलेक्ट हों।

तीसरी बात यह है कि अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मालिक को दें, उस पर जुर्माना करें वह चाहे तो बन्द करे, नहीं तो मजदूर बेचारे मारे जायेंगे। बन्द भी करें तो सिफ दो हफ्ते के लिये करें।

इसके बाद मेरी दलज्जा है कि :

खुद ही कातिल, खुद ही शहीद, खुद ही मुंसिफ ठहरे,

अक्रवा मेरे करें खून का दावा किस पर।

or Central Government and". The difficulty here is that it will defeat the very purpose of the provisions of clause 6, if this amendment is accepted. We want that no prejudicial material should be circulated. If the order of the Central or the State Government has to be obtained by the time this order of the Central Government or the State Government is obtained, the objectionable material will find such a wide pass the order after currency that it will be absolutely useless to that.

The purpose of this clause is to give the power to the District Magistrate so that he could immediately take action and seize any material which is intended to inflame communal and religious feelings thereby leading to violent disturbance and communal riots. Therefore this particular amendment is also not acceptable to us.

Shri Jha and Shri Misra have moved amendments whereby they want the role of the Press Advisory Committee to be reversed or changed a little bit. As far as Shri Misra's amendment is concerned, I would say that he wants to replace a very elaborate arrangement that we have laid down in the concerned clause by a simple one that he has suggested, namely :—

"Provided further that the authority making the order shall, without delay, refer the matter to a Committee to be known as Press Consultative Committee".

This would mean that as soon as the complaint is received the Government should refer the matter to the Committee.

SHRI SRINIBAS MISRA : After taking an action, the authority will refer it to the Committee.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : 'Authority' means 'governmental authority'.

If this amendment is accepted, the aggrieved party will be precluded from making a reference to the advisory committee which not be fair to the aggrieved party. The aggrieved party should also have the authority to approach the consultative committee and place their point of view before the committee. It should not be only the authority which should be able to approach or send the order to the committee, take its verdict and then either confirm or delete or amend the order. I think, it will not be in the interest of the parties themselves if they are excluded from making a reference to the

advisory committee. Therefore, I hope the hon. Member will not press his amendment.

Shri Shiva Chandra Jha has also suggested that after intimating the Press Consultative Committee this particular... (Interruption)

श्री शिवचन्द्र झा : कार्रवाई ग्राप के प्रफेसर करते हैं। यह इंस्ट्रक्शन उन को दे दिये जायें कि वह जो कार्रवाही करें उस को पहले प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी को बतलायें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have understood that. But here difficulty would be that the press consultative body will come into the picture only after a representation is received by it and not otherwise. Supposing, the consultative body does not receive a representation, there would be no need for the consultative body to go into the matter ; only when the aggrieved party makes a reference to it that it will come into play.

Then, I have already replied to Shri Jha's amendment No. 21 seeking to substitute "two months" by "one month." Amendment No. 22 is consequential to the earlier amendment.

Shri Viswambharan has made a suggestion regarding placing a restriction on the right of the Central Government. You, Sir, as an hon. Member of the Joint Committee which considered this measure, have given a dissenting note on this very subject and I would like to explain that by placing restrictions on the authority of the Central Government all kinds of serious practical difficulties would be created. While this matter was discussed in the Joint Committee, we had stated that although we were taking the rights for the Central Government officers to make an order under this clause, it would be used with a great deal of discretion and circumspection ; that it would not be used in a very lighthearted manner and that it would be used only when it was necessary to prevent a very inflammatory or a very irrational kind of literature from being circulated.

There is also another point which the hon. Member should consider. These kinds of documents, papers or newspapers, which have very highly inflammatory or communal writings which could lead to an outbreak of communal riots, are not limited in their

[Shri Vidya Charan Shukla]

circulation only to one State. They might be published in one State and circulating in two, three or four adjoining States. Therefore if the order is made by one State and the other States do not make the order simultaneously or quickly, the damage would be done.

Therefore, when it becomes a matter of inter-State operation, the order by the Central Government would be necessary. If we place the restriction on the Central Government and allow them to operate in Union Territories, I am afraid, the main utility of this particular provision will be completely gone.

Sir, I think, I have dealt with all the amendments that the hon. Members have moved and because of the reasons given, I am sorry I cannot accept any of their amendments.

MR. CHAIRMAN : Now I put all the amendments together to the vote of the House.

Amendments Nos. 6 to 9, 20 to 22, 30, 32 to 35 and 37 were put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 6 stand part of the Bill"
The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—(Penalty)

SHRI SHIV CHANDER JHA : I beg to move :

Page 5,—

for line 18, substitute—

"to one month, or with fine upto five hundred rupees, or with both." (23)

प्रिटर, प्रब्लिशर, एडिटर आदि को आपने सजा देने की इस में बात रखी है अगर वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो। आपने एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था की है। मैं चाहता हूँ कि इसको घटा कर आप एक महीना और पांच सौ कर दें।

एडिटर, प्रब्लिशर और प्रिटर की अहमियत जनतांत्रिक समाज में बहुत ज्यादा है। जफरसन

ने कहा था कि एक अख्बी सरकार और एक फ्री प्रेस में से अगर मुझे चुन करने के लिए कहा जाए तो मैं फ्री प्रेस को चुन करूँगा। उन्होंने कहा था कि फ्री प्रेस इज बेंटर दैन गुड गवर्नमेंट। आज के जमाने में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। प्रेस की अहमियत का तभी अंदाज हो गया था जब जान गूटन वर्ग ने प्रेस ईजाद किया था। उसके बाद जान लिलवर्ग ने लड़ाई लड़ी। मिलटन का अध्ययन आप करो और देखो कि वह फ्री प्रेस के बारे में क्या कहते हैं। इतना ही नहीं स्वातंत्र्य की लड़ाई जान पीटर यंगर ने न्यू यार्क के गवर्नर कास्बी के खिलाफ लड़ी थी जोकि प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने में लगा हुआ था। जान पीटर यंगर ने अपना छोटा सा प्रखबार निकाला और उसने संघर्ष किया। इस संघर्ष में वह सफल हुआ और अमरीका के स्वातंत्र्य की बुनियाद वहाँ से पड़ी। अखिर में अमरीका आजाद हुआ।

मैं तसफील में जाना नहीं चाहता हूँ। आप देखें कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं 19वीं सेंचरी के एडिटर को पसन्द करता हूँ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि वह किसी विचार को ले कर आगे बढ़ता था और जोर शोर से उसके लिए काम करता था, यों थपथपा कर लड़ता था, चापलूसी, चाटुकारिता से काम नहीं लेता था, आज की तरह बुर्जुआ, यैलो, प्रास्टीड्यूटिड प्रेस के एडिटर, रिपोर्टर्ज वगैरह की तरह नहीं था। नेशनल हेराल्ड लखनऊ से निकलता है और उनके ऊपर पंडित जी के ये विचार लिखे रहते हैं कि प्रेस का उद्देश्य क्या होना चाहिये। यह जो बुर्जुआ, यैलो, प्रास्टीड्यूटिड प्रेस है इसको खत्म होना चाहिये।

जो कलम उठाता है, अलबार लिखता है, वह एक बहुत बड़ा काम करता है। वह मानव समाज को चन्द्र लोक से भी आगे पहुँचाने का काम करता है। वह मानव समाज को मार्च तक, सूरज तक पहुँचा रहा है। उसको जब सजा

देनी हो तो उसका भी जरूरी आप ध्यान रखें। शोषसपीधर ने क्या कहा था, उस पर भी बिचार कर लें। उन्होंने कहा था कि जस्टिस शुड बी टेम्पटें विद मर्सी। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि एक साल की जगह आप एक महीना कर दें और एक हजार रुपये की जगह पांच सौ रुपये कर दें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The offence of contravening any order under the clause would be a serious matter. If we want to maintain communal harmony and peace in the society, we will have to see that those people who deliberately create such disturbances in the society or in the community are punished in a manner which will deter them to do or commit the same offence again.

Therefore, we have provided that there should be a punishment of imprisonment upto one year or fine upto Rs. 1,000. When I say, imprisonment upto one year or a fine of Rs. 1,000, it does not mean that in every case the punishment will be to that extent. It will be left to the court to award punishment looking to the severity of the offence and also the other circumstances of the case. (*Interruption*) This is the maximum limit. I think, the court should be given the discretion in appropriate cases to award a deterrent sentence. It is not necessary that in every case a deterrent sentence will be awarded; the court can award a punishment of imprisonment for two months or three months or whatever they decide in their wisdom. Looking to the objective that we want to achieve, it would be necessary to give this discretion to the courts. Therefore, I would not be able to accept this amendment.

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment 23 to the vote of the House.

Amendment No. 23 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—Composition of the Press Consultative Committee and rules in respect thereof

SHRI ABDUL GHANI DAR : I beg to move :

Page 5, line 21,—

after "editors." insert—

"elected representatives of" (10)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 5, line 21,—

after "being" insert—
"economists". (24)

SHRI P. VISWAMBHARAN : I beg to move :

Page 5, line 22,—

add at the end—

"and shall be selected out of panels of names to be submitted to the Government by the respective accredited organisations or associations of editors, journalists and publishers." (36)

श्री शिव चन्द्र झा : प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी सरकार बनायेगी। यह कहा गया है कि उस में एडिटर रहेंगे, पब्लिशर रहेंगे, जरनलिस्ट रहेंगे और इस सब को रूज में प्रेसकाइब किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस में इकोनोमिस्ट को भी शामिल किया जाए।

आप कहेंगे कि यह तो प्रेस की बात है, अर्थ शास्त्री का इससे क्या ताल्लुक। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जो हालत चल रहे हैं उन में आप अर्थ शास्त्री को इगनोर नहीं कर सकते हैं। कदम कदम पर आपको उसकी सलाह की जरूरत होगी। इस वास्ते उसका रहना बहुत जरूरी है।

अर्थ शास्त्री की ग्रहमियत को आप पहचानें। अब तो नोबल प्राइज इकोनोमिस्ट को भी मिलने जा रहा है। अब तक यह साइंस और लिटरेचर के फील्ड में ही काम करने वाले लोगों को दिया जाता था। अब इकोनोमिस्ट को भी यह मिलने जा रहा है। इसी से इकोनोमिस्ट की ग्रहमियत जाहिर हो जाती है। इसको लागू करने के लिए आपको उसकी भी सलाह लेनी होगी, उससे भी माइवरा करना होगा। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि इकोनोमिस्ट को भी इस में जोड़ दिया जाए।

श्री अब्दुल गनी डार : मुझे इतना ही कहना है कि एडिटर, पब्लिशर और जरनलिस्ट से पहले इलैक्टिड सफ़र जोड़ दिया जाए। इन्होंने कहा है कि रूज बनाये जायेंगे। अब वे कैसे बनेंगे, कितना टी ए और बी ए लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह सब तो या तो मिनिस्टर के दिमाग में होगा या डिपार्टमेंट के दिमाग में होगा। जो खतरा है उसको महसूस

[श्रीअब्दुल गनिदार]

करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये चुने हुए होने चाहियें। अगर वे इलक्टिड होंगे तो इसको भी वे देखेंगे कि सरकार जो एक्शन ले रही है वह ठीक है या नहीं और उसके साथ साथ वे इस बात का भी ख्याल करेंगे कि हम को शम शानी चाहिये कि हमारे कुछ साथी इस तरह से चलते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे फिरका परस्ती बढ़ती है। इस बास्ते अगर मेरी एमेंडमेंट को मान लिया जाए तो मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँगा।

हमेशा आप अपने बल पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब भी आप अपने बल पर, इकट्ठे हो कर चलें आपस में लड़ न मरें।

[श्री عبدالغنی ڈار - مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ ایڈیٹرز اور جرنلسٹ سے پہلے ایکٹو لفظ جوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رولز بنائے جائیں گے اب وہ کیے نہیں گئے۔ کیسے نہیں ہیں گئے۔ سب ٹی اے اور کتا ڈی اے میں گئے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ یہ سب تو بات سننے کے دماغ میں ہوگا۔ یا ڈیٹمنٹ کے دماغ میں ہوگا۔ جو خطہ ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں۔ یہ پیسے ہوتے ہوتے چاہیں۔ اگر وہ ایکٹو ہوں گے تو اس کو بھی وہ دیکھیں گے کہ سرکار جو ایکشن لے رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی خیال کریں گے کہ ہم کو شرم آتی چاہئے کہ ہمارے کچھ ساتھی اس طرح سے جلتے ہیں اس طرح سے بھی یہ حرکت ہے جس سے فرقہ پرستی ہوتی ہے اس واسطے اگر میری اینڈمنٹ کو مان لیا جائے۔ تو میں شرف مند ہوں۔

بیش آپ اپنے بل پر چلے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بھی آپ اپنے بل پر چلے آگے ہو کر جیوں۔ آپس میں لڑ مرس۔

SHRI P. VISWAHMBHARAN: According to this Clause, a Press Consultative Committee will be constituted consisting of such number of persons, being editors, publishers and journalists, as may be prescribed by rules made under this section. The reports of the Joint Committee says:

"During the course of discussion on Clause 8, the Minister in charge of the Bill explained that the proposed Press Consultative Committee at the Centre and the State level will consist of 10-15 members and 7-10 members, respectively..."

"...and that the members of the Committees would be chosen by Government in consultation with the representative

organisations of editors, newspaper managements and journalists. The Government would invite panels of names from representative bodies like the All India Newspapers Editors' Conference and choose the persons to be appointed as members of the Consultative Committee out of the names suggested by such representative body."

If this is the intention of the Government, I would urge upon the Government to make these provisions in the Act itself. These assurances of Ministers are not very often followed by action. Very often in this House we hear complaints of assurances not being fulfilled. The State Governments have to constitute Press Consultative Committees. This assurance in the Joint Committee or here in this House may not be binding on the State Governments. So, if really the Government's intention is as mentioned in this report, then there is no harm in incorporating this in the Act itself. Not only there will be no harm but it will only help the implementation of the Act in the direction in which this Government wants to do. So I move my amendment that the members of the Press Consultative Committee shall be selected out of panels of names to be submitted to the Government by the respective accredited organizations or associations of editors, journalists and publishers.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: May I say a few words.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: This is an important clause, Sir.

MR. CHAIRMAN: It is a departure from the procedure we are following. We are very much behind the schedule. Anyway, you can take a few minutes.

श्री श्रीचन्द गोयल: सभापति महोदय, यह ठीक है कि मन्त्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया है कि वह समाचारपत्रों के सही प्रतिनिधियों को इस कमेटी में स्थान देंगे। लेकिन पिछला अनुभव कुछ और ही है। जब इमर्जेंसी डिक्लेयर हुई, उस समय भी जो प्रतिनिधि एक

पैनल के रूप में समाचारपत्र-प्रतिनिधियों की संस्थाओं ने दिये, उन को सरकार ने कई बार माना और कई बार नहीं माना, सरकार ने प्रइचने पैदा की, उस ने कहा कि अमुक व्यक्ति हमें मान्य नहीं है और अमुक व्यक्ति हम चाहते हैं।

मैं समझता हूँ कि समाचारपत्र-प्रतिनिधियों की संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति इन संस्थाओं में उन का प्रतिनिधित्व करेगा। सरकार को पिक एंड चूज—किसी को लें, किसी को न लें—की पालिसी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर इस कमेटी में सात आदमी लेने हैं, तो आठ, नौ या दस आदमियों का पैनल होना चाहिए; यह नहीं होना चाहिए कि सरकार ने पांच आदमी लेने हैं और उस के बीस आदमियों का पैनल देने के लिए कहा जाये। इस कानून की मंशा से सम्बन्धित विषयों का निर्णय समाचारपत्र-प्रतिनिधियों की संस्थाओं द्वारा चुने गये व्यक्तियों के सलाह-मशवरे से ही होना चाहिए। इस में सरकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : During the consideration in the Joint Select Committee this point was discussed at some length and there an assurance was given that the Consultative Committee will be selected out of the panel that may be suggested by accredited associations of editors and publishers and writers, etc. and so far whenever such Advisory Committees have to be formed, they have always been formed in consultation with the bodies for whose benefit this Consultative Committee or Advisory Committee has been appointed. Therefore, this assurance has not only been given but it has been incorporated in the report of the joint Select Committee. Therefore, I do not think it would serve any useful purpose if this is incorporated in the Bill itself.

So, I do not think these amendments can be accepted.

श्री शिव चंद्र भट्टा : मन्त्री महोदय ने कमेटी

में इकानोमिस्ट्स को सम्मिलित करने के बारे में कुछ नहीं कहा।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am coming to that.

As far as the question of the economist is concerned, I must confess that I fail to understand what an economist will do in a Criminal Law Advisory Committee.

श्री शिव चंद्र भट्टा : गांधीजी पहले जर्नलिस्ट नहीं थे। इसी प्रकार तिलक भी पहले जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा और केसरी का सम्पादन किया। अन्य क्षेत्रों में ख्याति-प्राप्त व्यक्ति, जिन में इकानोमिस्ट्स भी होते हैं। जर्नलिज्म में आ जाते हैं। इस लिए मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी में इकानोमिस्ट्स को भी स्थान दिया जाये।

MR. CHAIRMAN : Minister did not yield. But you made a speech. All right.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I share the high opinion about economists with the hon Member. But I think they will be ill at ease in a committee like this where only criminal law matters are discuss and an economist may not be able to contribute anything. There, I am not be able to contribute anything. There, I am not accepting these amendments. There is also another amendment just the same as Shri Abdul Ghani Dar's amendment. I oppose all the amendments.

MR. CHAIRMAN : I will put all the amendments to Clause 8 to the vote of the House.

Amendments No. 10, 24 and 36 were put and negatived

MR. CHAIRMAN ; Now the question is :

"That clause 8 stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 8 was added to the Bill

MR. CHAIRMAN : There is an amendment to Clause 1.

[Mr. Chairman]

Ameedment made :

Page 1, line 4,

for "1968" substitute "1969" (2)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. CHAIRMAN : The question is.

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN : For the Enacting formula, there is a Government amendment.

Amendment Made :

Page 1, line 1,

for "Nineteenth" substitute "Twentieth" (1).

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. CHAIRMAN : Now the question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed"

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

That the Bill, as amended, be passed." I may inform the wise that the time allotted for this Bill was 3 hours. We have already taken 5 hours and I have got a few names with me for the Third Reading.

SHRI ABDUL GHANI DAR : I will take just 3 minutes only.

MR. CHAIRMAN : Let me please be allowed to complete what I wanted to say. So, I request Members to be very brief, as possible. Shri N. K. Somani.

SHRI N. K. SOMANI (NAGOUR) : Government must realise before they bring

in any particular piece of legislation or amendment and putting it on the statute book whether the country is prepared to accept that and whether it is possible for them and for the executive authority to implement that in letter and spirit. Yesterday, I brought to the attention of the House that the proposals which were made regarding the Gold Control (Amendment) Bill were not possible of achievement or execution. I would like to repeat the same plea. Whatever one may claim about the progress made in the various fields in this country one cannot deny that all kinds of considerations based on community, based on caste, based on obscurantism, are pervading the political social and economic life of the country. So I wish to impress upon the Minister that he should look into it thoroughly and we should see that the necessary public opinion is created. The education should be imparted when the child is young, whether it is community development programmes, or the All-India Radio, but these are being utilised for some other purposes. We have to see that, whatever programmes we have, we should channelise the energy and the attitude of the people. Clarity should also be brought into this.

15.00 hrs.

As far as communal riots are concerned, I remember that during the British times, a very fine scheme of mohalla fines used to be enforced so that if there were some miscreants or some misdirected people in a particular mohalla, the entire mohalla was subjected to a community fine and this used to bring a great deal of pressure on those miscreants and it used to set matters right. This is a kind of thing which Government must in extreme cases include in measures like this,

I would like to warn and caution Government at this stage against arming the executive authority with such disproportionately large powers. One can give the benefit of doubt to certain kinds of governments but it is not impossible today to imagine that in either a few days' time or even a few years' time there might be some other kind of Government sitting there which might openly wreck the Constitution of this country. Therefore, in respect of all these

powers that Government are trying to invest themselves with, the only test according to me would be not what a well-intentioned or democratic government is likely to do, but what a party which is wedded to and has openly declared its resolve to wreck the Constitution, whether it is in government or not, will do. What will happen when such a government comes in the face of these disproportionately high powers that Government are now arming themselves with ?

As far as this particular Act is concerned, I suppose Government have given authority to policemen through the channels of the State Government to raid or to enter into places of worship. I do not know how Government are going to find out what is going on inside a temple or a mosque or gurudwara unless they send their policemen inside, which I think is going to be a gross violation of freedom of worship.

Similarly, Government are taking powers to take action against a printing in press in respect of certain documents or pamphlets which are likely to be printed in future or liked to be printed in future or which are on the bed of the machine so that they may be prohibited from being printed. This again is a power which I think is disproportionate to the needs. If a pamphlet or document or matter has been printed, Government are at perfect liberty to take any action, but to presume that something is likely to be done and then take action is, I submit, going a bit too far.

While I consider all of us responsible in this country for the obscurantism that we have, for the backwardness that we have, for the caste and regional considerations that we have, so long as each one of the applies and exploits these baser instincts of people, I do not think that this particular piece of legislation which is going to be put on the statute-book is going to solve any matter, as far as the announced intentions of this Bill are concerned. I think that the root of the problem will have to be solved by this Government. For this, firstly, Government will have to educate public opinion and create a healthy public opinion in this country so that these undesirable things will have no place in our life or in our actions or in our minds. The second suggestion which I have made and which is a long-term one is to solve the economic problems of this country so that not only our moral but our

material gains would go up. I hope that all these considerations will weigh with Government when this Bill becomes law.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, इस बिल की भावना का मैं स्वागत करता हूँ। बिल के पीछे जो भावना है कि इस देश में साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव न हों और सही प्रजातंत्र देश में आए उस के ऊपर कोई मतभेद नहीं हो सकता। यह बात भी सत्य है कि इस देश में प्रजातंत्र एक ढोंग बन गया है और जो प्रजातंत्र के नाम पर चुनाव आदि होते हैं वह जाति, भाषा और जन्म आदि के नाम पर, उस का अनुचित लाभ उठाकर लोग ऊपर आते हैं और सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। परन्तु बीमारी कहाँ है ? अध्यक्ष महोदय, बीमारी सर में है और गृह मन्त्री महोदय ने पट्टी पर में बांधने की कोशिश की है। इस तरह इलाज हो सकेगा इसमें संदेह है। बीमारी राजनैतिक नेताओं के, लीडर्स के दिमाग में है, जनता में नहीं है। मन्दिर मस्जिद, और गिर्जों में नहीं है। पोलिटिकल लीडर्स के दिमाग में बीमारी है। उन का इलाज होना चाहिए। उन का इलाज तो किया नहीं। भारत-वर्ष की आजादी के पश्चात् जब से चुनाव का दौर चला है, अर्थात् आजादी से पहले इस देश में एकता थी। देश एक साथ मिला हुआ था। यहाँ प्रान्त की भावना नहीं थी भाषा की भावना नहीं थी, साम्प्रदायिकता की भावना भी देश में नहीं थी। अंग्रेजों के समय में हिन्दू और मुसलमानों में कुछ भेद था लेकिन वह भी उन्हीं का पैदा किया हुआ था। देहात और गांव में वह चीज भी नहीं थी। लेकिन राजनैतिक नेताओं ने अपनी गद्दी की खातिर इस देश में नये नये नारे लगाए। प्रान्त के नाम पर, भाषा के नाम पर न सालूम क्या क्या भगड़े और क्या क्या नारे खड़े कर दिए। आज यह बीमारी फैलती जा रही है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों बीमारी भी बढ़ती जाती है। आप ने कानून बनाया है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। आप ने इस बिल की धारा के अनुसार बहुत दूर

[श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

तक कदम रखा है जहाँ आप को रखना भी नहीं चाहिए था। आप ने कहा है कि कोई जाति के नाम पर, प्रान्त के नाम पर भड़काए तो उस को आप इस की सजा देंगे, यह तो ठीक है। चाहिए तो यह था कि राजनैतिक नेताओं से मिल कर इस प्रकार का फैसला कर लेते कि जहाँ जिस जाति के लोगों की मेजरिटी होगी वहाँ उस जाति का प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा। मुसलमान जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ हिन्दू कैंडिडेट खड़ा किया जायगा और जहाँ हिन्दू ज्यादा होंगे वहाँ मुसलमान या दूसरा कोई खड़ा किया जायगा। यह आप मिल कर एक फैसला ऐसा कर लेते तो अच्छा था। मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ। हर एक पोलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट्स का चुनाव करने लगती है तो मूल आधार उस का यही होता है कि उस क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं। यह स्थिति आज है। मेरा आक्षेप यह है कि इस बिल के द्वारा लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर आप ने आक्षेप किया है। यदि कल को कोई कोर्ट में जा कर चैलेंज करेगा तो आप को फिर विधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तीसरे और दूसरे क्लॉज में जो बात आप ने कही है :

Whoever commits an offence specified in sub-section 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies.

मैं पूछना चाहता हूँ यह मन्त्री महोदय से वशिप का तरोका, चुनाव हों या न हों, संसार भर में एक है। उसे कोई नहीं बदल सकता। आप कानून बनाएं या न बनाएं। हर धार्मिक सम्प्रदाय का अपना पूजा करने का एक ढंग है। उस से चुनाव का क्या सम्बन्ध आता है? लेकिन आप ने उस पर नियन्त्रण किया है। रेलेजस सेरीमनीज पर भी आप ने प्रतिबन्ध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, दो चीजें होती हैं मन्दिरों में एक सर्मन्स है, एक वशिप है। वशिप इन्वॉसेंट है। उस में किसी के चुनाव से कोई संबंध आता नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, इस में वशिप को ला

कर आप ने कौन सी बात सोची है और कौन सी वशिप ऐसी है जो चुनाव पर असर डालती है? हाँ, उपदेश पर आक्षेप हो सकता है कि मन्दिर और मस्जिद में लोगों ने इन स्थानों का दुष्प्रयोग कर के वहाँ राजनैतिक भाषण देने प्रारंभ किए हैं और वह चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, इस से मैं सहमत हूँ और इस पर आप को प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। परन्तु उस में ऐसा आप जोड़ देते कि चुनाव के अवसरों पर अगर इस प्रकार का भाषण करें तो वह अनुचित होगा। मगर ऐसा नहीं है। आप ने यह किया है कि जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी प्रवचन देगा—मैं ने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, संसार में जितने धार्मिक सम्प्रदाय हैं, उन में इस तरह के मतभेद हैं कि एक धार्मिक सम्प्रदाय वाला जिस समझ अपने सिद्धांत का प्रचार करेगा दूसरे सम्प्रदाय को उस से ठेस पहुँचेगी ही। मगर मैं पूछता हूँ कि एक ही मन्दिर में एक ही सम्प्रदाय के लोग बैठे हुए हैं और अपने सिद्धांत की चर्चा करते हैं, उस पर सोचते विचारते हैं तो उन पर प्रतिबन्ध कैसा? यह मेरी समझ में नहीं आया। यह तो हो सकता है कि चुनाव के संबंध में जब भाषण दें, राजनैतिक भाषण कोई दे तो उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। मैं जानता हूँ जहाँ आप का इशारा है वहाँ आप की हिम्मत आज भी नहीं होगी। जिस कारण से आप बिल बना रहे हैं मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वहाँ चुसने की आप को हिम्मत नहीं होगी। जहाँ इस प्रकार के भाषण होते हैं और जो धर्म को और पालिटिक्स को एक बना कर चल रहे हैं वहाँ क्या हिम्मत करेंगे आप? आप नहीं कर सकते हैं। इस बिल की भावना का मैं स्वागत करता हूँ परन्तु इस से इलाज हो सकेगा, इस में मुझे सन्देह है। मन्दिर, मस्जिद तथा गिजावर के अन्दर जाकर आपने जो उस में हस्तक्षेप किया है, वह 19वीं चारा में जो उन को राईट है फ्रीडम आफ वशिप की उस पर आप ने आघात

पहुंचाया है। अब तो आप यह बिल पास करने ही जा रहे हैं, शुक्ला जी तो हर एक के अमेंडमेंट को भाड़ मार कर खत्म कर देते हैं, यह मैं ने उस दिन कहा था कि आप ने कहा कि संभल कर बोलिए जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जब वे पूजा करेंगे तो जो उसमें विश्वास नहीं करते उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। यहां पर डार साहब बंटे हैं, जब गोकुशी का दिन आता है, बकरा ईद आती है, यह एक त्योहार होता है लेकिन उगसे बहुत से लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं कहता हूँ यह विधेयक कैसे चलेगा? या तो आप सेक्युलरिज्म के प्राधार पर कह दीजिए, सभी की धार्मिक पुस्तकों को मंगा लीजिए और एक फामूला निकाल दीजिए कि इसी को मानना पड़ेगा इस पर मुझे कोई प्राक्षे नहीं होगा। इसलिए मेरी पुनः प्रार्थना है कि इस बिल को पास करने से पहले पुनः सोच लीजिए कि आप—बया करने जा रहे हैं। यह बीमारी राजनीतिक लीडर्स के दिमाग में है, जनता के दिमाग में नहीं है लेकिन आप जनता के ऊपर कानून लादने की कोशिश कर रहे हैं, डंडे के द्वारा जनता को पीटना चाहते हैं जबकि पिटाई लीडर्स की होनी चाहिए। इन शब्दों के माय में आपको धन्यवाद देता हूँ और सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बिल में संशोधन करें।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandi-wach): The object of this Bill is quite laudable. The object is to prevent and remove communal and regional tensions. But this Bill is again going to be an addition to the armoury of Government. Already Government have too much power; they are armed to the teeth and are not able to use the legislation against the culprits. They have shown their power-hunger by wanting to have more and more powers in their hands. The Government is just like a soldier carrying too many guns on his shoulders with the result that at the right target and at the right moment he may not be able to shoot. This may happen with this Government also.

The Bill, as I said, gives Government enormous powers, powers so wide that they

can be misused at any time. So Government must be very cautious in using this legislation. Honest criticism and fair comment should not be stifled. I am afraid these will be brought within the Act now. We must be very careful to see that free and frank expression of opinion is not stifled.

The wide powers given to Government under this Bill can bring within their purview activities of people based on their place of residence or region. The language agitations or even border disputes can be brought within the mischief of this Bill. Under this, those agitating on either side in the Mysore-Maharashtra boundary dispute can be arrested, even the two Chief Ministers can be arrested for putting forward their respective claims. In the language agitation, many Chief Ministers are involved. If strictly implemented, they can all be arrested under this Act, So I warn Government that though they will get it passed through their majority here it should be used very scrupulously and cautiously.

As has been pointed out by Shri Viswambharan, cl. 6. empowers the Central Government to authorise anybody, any magistrate to sanction a prosecution, Already, State Governments are there to look after law and order. The Central Government must, therefore, empower the State Governments to launch prosecution.

The revisions against printing presses should be used very sparingly because under the same a printing press can be closed consecutively for two months. Many of the small newspapers, weeklies and monthlies are printed in these small presses and if they are closed, they will be affected. So the utmost care should be exercised in the use of this power and the order should be operative for the minimum period, where it is absolutely necessary.

श्री लताफत अली खां (मुजफ्फरनगर) : चेयरमैन साहब, यह बिल नेशनल इन्टिग्रेशन कौशिन के फौमनों को घमली जामा पढ़ाने के लिए लाया गया है। इसका मकसद यह है कि जबान, नस्ल, सूबा और इलाके के नाम पर जो फसादान पैदा किये जा रहे हैं उनको रोका जा सके। लेकिन खाली बिल लाने से काम नहीं चलेगा। घाप कितनी ही सब्ती कर दीजिए लेकिन वह बेकार है। देखना यह होगा कि

[श्री लताफत अली खां]

किसी कानून पर किस तरह से अमल किया जाता है। अगर अमल ठीक तरह से होगा तो काम भी होगा, अगर ठीक तरह से अमल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। पिछले दिनों इसी सिलसिले में मुकदमा चलाये गए थे। जो अखबारात ऐसे भगड़े पैदा करने हैं, फिरकापरस्ती फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने थे। लेकिन ऐसे अखबारात को चुनने में, गवर्नमेंट के अफसरान ने खानिम फिरकापरस्ती का मुजाहरा किया। जिनने अखबारात के खिलाफ मुकदमें चले उनमें 85 फीसदी ऐसे हैं जिनको मुसलमान निकालते हैं। इसमें मुल्क में गलत तास्मुव पैदा हुआ। क्या मुल्क में सिर्फ मुसलमान अखबारात ही ऐसे हैं जो फिरकापरस्ती फैलाते हैं? मुल्क के बुरत अखबारात ऐसे हैं जो मुसलमान 22 सालों से मुसलमानों के खिलाफ मजामीन लिख रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसपर अमल होगा इसको देख कर के किया जाना चाहिए—खास तौर से किमी फिरके को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बिल में एक लात की कमी रखी गई है। और वह यह है कि एडमिस्ट्रेशन और पुलिस अगर फसादात के मौके पर जानिबदारी का सबूत दें तो उनके लिए इसमें कोई दफा नहीं लाई गई है जिस से उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सके। पिछले दिनों मऊ में भगड़ा हुआ, वह फिरकेवाराता भगड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर जो रोल अदा किया, मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जुल्म किए, उनपर कोई तवज्जह नहीं दी गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल में ऐसी दफात होनी चाहिए कि अगर अफसरान अपनी अहमियत का सबूत न दें तो उनके खिलाफ भी ऐक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह की बात इसमें जरूर आ जानी चाहिए कि अगर किमी इलाके में भगड़ा होता है, कोई ऐसी बात पैदा हो जाती है तो वहां के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी ऐक्शन लिया जायेगा, उनकी तवज्जुजी की जायेगी, तबादला

किया जायेगा। अभी पिछले दिनों मऊ में जो भगड़ा हुआ उसमें यह कहा गया कि वहां के अफसरान जानिबदारी का सबूत दे रहे हैं, उनका तबादला कर दिया जाये लेकिन उसपर कोई तवज्जह नहीं दी गई। नेशनल इन्टिग्रेशन काँसिल में भी तै किया गया था कि ऐसे अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाये लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी एक और जहिनियत इन्दौर के भगड़े में देखने में आई। वहां पर एक फिरके के मजदूरों ने अहमियत के मजदूरों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया। यह बड़ी खतरनाक जहिनियत है। अगर इस को बढ़ावा मिला और कानून से इसको रोका नहीं गया तो यह जहिनियत सिर्फ काग़्खानों तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि और भी आगे बढ़ेगी। स्कूलों में भी इस बात का मतलब हो सकता है कि अगर एक फिरके के तालिबान बँटेंगे तो म नहीं बँटेंगे। अस्पतालियों में भी यही बात हो सकती है। इसी तरह से यह बढ़ती चली जायेगी। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कहां-तक बढ़ती चली जायेगी। इस बिल में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं समझता हूँ यह बिल नाकाफी है।

इसके अलावा इसमें इबादतगाहों में प्रोपेगैंडे के लिए दफा रखी गई है। लेकिन यह ख्याल करना कि सिर्फ इबादतगाहों में ही प्रोपेगैंडा होता है, बिस्कुल गलत होगा। आज कालेजों में ऐसे कैम्पस लगते हैं जहां पर फिरकापरस्ती की तालीम दी जाती है, स्कूलों में तालीम दी जाती है। बहुत से सरकारी कारखाने हैं जहां पर इस किस्म का प्रोपेगैंडा चल रहा है। इसलिए इन सभी बातों को इसमें शामिल कर लिया जाता ताकि गडबड़ फैलाने का अन्देशा अगर है तो उसको रोका जा सके।

इसके अलावा इस बिल में इस बात की भी गुंजायश रख दी जाती कि इस तरह का कोई भगड़ा हो तो उसकी जुडीशियल तहकी-

श्री शिवचन्द्र भ्वा : इस विधेयक का मकसद सभापति जी, फिरकापरस्ती को रोकना है जो प्रकाशन के माध्यम से आती है। जहाँ तक फिरकापरस्ती बैठकों से और और जगहों से निकलती है उसके मुतालिक तो माननीय त्यागी जी ने बहुत कुछ कहा। लेकिन प्रकाशन के माध्यम से जो फिरकापरस्ती निकलती है और जिसको सरकार रोकना चाहती है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उसके लिये यह कानून इनडिफैक्टिव होगा, कारगर कतई नहीं होगा। जिस चीज को यह रोकना चाहते हैं, चीजें प्रकाशित की जायेंगी इसलिये नहीं कि उनका प्रकाशन होना चाहिये, बल्कि इसलिये कि वह एक बाई प्रोडक्ट है, वह सेन्सेशनलिज्म है। और चाहे छोटा अखबार हो या बड़ा, उसकी वह खुराक होती है।

आप देखें इस सदन में जब हो हल्ला होता है तो पत्रकार लोग गर्दन ऊंची करके देखने लगते हैं। शेक्सपीयर और मिल्टन की बात पर उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर हो हल्ला करा जाय तो प्रेस रिपोर्टर जैसे मरे पर गिद्ध टूटते हैं इसी तरह से अखबार वाले दीड़ने लगते हैं, और यह बात ओवर आल हिन्दुस्तान के प्रेसों में है। इसलिये यदि हकीकत में आप चाहते हैं कि छोटा या बड़ा अखबार हो उसके माध्यम से फिरकापरस्ती की बात न निकले तो लाजिमी हो जाता है कि इस प्रेस पर आप कब्जा करें, राष्ट्रीयकरण करें। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि कल राज्य सभा में एक अज्ञानी मंत्री, जिस को प्रेस का ज्ञान नहीं है, न राष्ट्रीयकरण का ज्ञान है, ने राज्य सभा में यह कहा कि प्रेस का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेस का देश में राष्ट्रीयकरण होगा। भारत का मौजूदा प्रेस कतई ठीक नहीं है। यहाँ फ्रीडम आफ दी प्रेस नहीं है बल्कि मालिकों का फ्रीडम आफ दी प्रेस है।

हेराल्ड लास्की ने कहा कि मोडर्न प्रेस रिफ़ोर्मेसन है हमारे सिस्टम का। यह प्रेस के राष्ट्रीयकरण से घबराते हैं क्योंकि उसका

मतलब नहीं समझते हैं। प्रेस राष्ट्रीयकरण का का मतलब है कि जिसका हायर सर्कुलेशन हो, 10,000 से ऊपर उसका राष्ट्रीयकरण कर दो। लेकिन जनतंत्र में नुकताचीनी की गुंजाइश होनी चाहिये, इसको मैं मानता हूँ। इसलिये क्या तरीका हो? मेरी राय में जो मान्य पार्टियाँ हैं उन पार्टियों को बढ़ाने के लिये आप केन्द्रीय बजट से सबसिडी दें प्रेस को प्लान्ड प्रोग करें। जो वैयक्तिक प्रेस है उनका राष्ट्रीयकरण करें और मान्य पार्टियों को वह प्रेस ऊंचा करे। यह प्रेस नुकताचीनी के लिये होगा और तभी सही मानों में फ्रीडम आफ दी प्रेस कायम होगी। प्लान्ड प्रेस और पार्टी प्रेस के माध्यम से जब प्रेस का संचालन होगा तभी पब्लिक ओपीनियन सही आयेगी और यह सेन्सेशनल प्रेस नहीं रहेगा, बल्कि साफ विचार आयेगे और छोटे अखबार फिरकापरस्ती के लिये नहीं निकल सकेंगे और तभी हकीकत में में यह सरकार इफैक्टिव हो सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझको वाबजूद हमदर्दी होने के, थोड़ा शक रह जाता है कि कहां तक यह कारगर होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि यह मकसद पर पहुँचे। लेकिन जो गांधी जी ने कहा था कि इनका गेंड हाई है पर मीन्स ऊंचे नहीं हैं इसलिये मुझको शक लगता है कि कहां तक यह कारगर और कामयाब होगा। इन शब्दों के साथ मैं क्वालीफाइड समर्थन करता हूँ।

श्री अब्दुल गनी डार : सभापति जी, मैं अपने भाई शुक्ला जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब से कश्मीर में नेशनल इंटेग्रेसन काउंसिल हुई उसके बाद से कम्युनल रायट्स, लिगुअल रायट्स, टेरीटोरियल रायट्स और जमाती रायट्स बहुत बढ़ गये हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। क्यों बढ़ गये? अगर इस पर तवज्जह दें कि अखबारों द्वारा बढ़ गये तो मेरा ख्याल है कि वह पायेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर वह विचार करेंगे कि पब्लिशर या प्रिन्टर के जरिये बढ़ गये तो यह ख्याल करेंगे कि ऐसा नहीं है।

मैंने श्रीम प्रकाश त्यागी जी की बातों को, जो मेरे पूजनीय हैं, बड़े ठंडे दिल से सुना। मेरा ख्याल है कि इनका यह मतलब नहीं है कि भ्रगर कोई संध्या करे या गुरू-ग्रंथ साहब का पाठ करे, या कोई नमाज पढ़े तो उस पर इनको रेड करना पड़ेगा। जो भी मन्दिर, मस्जिद, गुरद्वारे में जायेगा उन की स्वाहिशा जरूर होगी कि भ्रदब के साथ वहां जाय। जरूर रेड करें भ्रगर कोई फिरकापरस्ती का प्रचार करता है इलेक्शन के जमाने में तो उस को साफ कर दें, और हर समय के लिये करना चाहिये। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। भ्रगर कोई मस्जिद में फिरकापरस्ती करता है तो भ्रदब रख कर उस पर रेड कर सकते हैं मुल्क के अमान के लिये।

दूसरी बात माननीय त्यागी जी ने कही कि अम्बुल गनी दार को एतराज हो सकता है। लेकिन मैं उनसे अर्ज करन चाहता हूँ कि वोलेंटरिली मुसलमान अपना हक कुरबान कर दें। भ्रगर हिन्दुओं का दिल दुबे। पैगम्बरे खुदा की इस बात को मानते हुए कि भ्रगर तुम्हारे कदम से एक भाई का दिल दुखता है तो उससे खुदा का अर्श हिलना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिसमें किसी को भी तकलीफ हो।

मैं कहता हूँ कि भ्रगर हम तरह का कोई काम होता है जो मुल्क के खिलाफ पड़ता है तो जरूर आप पाबंदी लगायें। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी के साथ जुल्म न हो। अक्सर देखा गया है कि गलन नाम पर भी गाय कट गयी और भ्रग्वबारों में गलत रिपोर्ट धाया हो गयी तो हजारों मुसमान काटे जाते हैं। रात को गांव बसता है और सुबह उसका नामोनिशान तक नहीं रहता।

मैं भाई शुक्ला जी से अर्ज करूंगा कि प्रेस पर जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, प्रेस के मामले में जो करने जा रहे है उसमें किसी का कोई भ्रगडा नहीं है। उस पर जरूर ध्यान करना चाहिये।

कुछ लोगों ने यह दलील दी है कि नेशन-लाइज कर लो प्रेस को। इससे तो एक ही तबला होगा। मन चे मिसरायम व तम्बुरये मन चे मिसरायत। मैं क्या गा रहा हूँ, मेरा तम्बूरा क्या गा रहा है। वह तो सरकार की बात भ्रलापता रहेगा। किसी पार्टी की कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन मुझे एक डर यह है कि जैसा उन्होंने कहा आज रीजनल भ्रगडा होता है, दो मिनिस्टर होते हैं, वह आपस में लड़ते हैं। वह कहते हैं कि यह मेरे इलाके में भ्राना चाहिए दूसरे कहते है कि हमारे में भ्राना चाहिए। चण्डीगढ़ का सोदा हो रहा है। उस पर वोटिंग होती है। उसमें मैं क्या करूँ और कोई क्या करे? लेकिन क्या श्री शुक्ला जी उनके ऊपर मुकदमा चलायेंगे? भ्रगर मेरी बहन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्र-पति गांधी जी की जन्म शताब्दी के वर्ष में जगजीवनराम को प्रेजिडेंट बनाना चाहिए तो क्या इस पर यह कहा जायेगा कि उन्होंने ने फिरकापरस्ती फैलाया। या भ्रगज जो जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने लिखा है कि निजलिगप्पा स्वतन्त पार्टी और जनसंघ के लीडरों स क्यो मिले तो उन पर मुकदमा चलाया जायेगा? मेरा यकीन है कि श्री शुक्ला के दिमाग में ऐसी बातें नहीं हैं। उनके दिमाग में सही फिरकापरस्ती को मिटाना मकसूद है। इम्प्लिमंटेशन वह खुद करे, बड़ उनक हाथों हो या कम्पूनिस्ट पार्टी के हाथों हो, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं।

اثری تبلیغی ڈارو ڈو نہ۔ سب سے بڑی میں اپنے جانی بھائی کی وجہ اس طرف
 دانہ جاتا ہوں سب کے بھائی ہیں۔ میں نے سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 گھر کی رکش میں جو میں نے رکش اور میں نے رکش میں سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 راولپنڈی میں ہے۔ میں نے سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 میرا خیال ہے کہ وہ پانچ لاکھ کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 پانچ لاکھ کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی

میں نے بیابانی کی باتوں کو بڑے خندہ سے دل سے سنا۔ میرا خیال ہے کہ ان
 کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔
 پڑھے تو اس پر ان کو کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔
 وہ سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 پانچ لاکھ کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 ان کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی سب کے ساتھ ساتھ ہی
 وہ کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔ ان کو کوئی سزا دینی ہے۔

دوسری بات تھی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹیلیجنٹ انسان چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے پینل پر حصر کر کے رکھ دیا جائے جو ان کے لئے مناسب ہے۔ اس سے پھر ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔

society and nation, those people will be disqualified under the law to hold any elected office. This is one thing that is being done here.

I am not claiming that this covers all the contingencies. But whatever contingencies we can visualise have been covered in this. As I said earlier, there are many things which are already covered under various statutes that have been enacted by this honourable House earlier. So, it is not that this is a complete measure to contain any fissiparous tendencies or to contain those people who are seeking to encourage such tendencies.

Certain misgivings have been expressed regarding the implementation and I would say that the Government of the day, whichever Government it may be, if it works under the democratic Constitution, will be answerable to the elected representatives of the people and whatever policies of the Government may be, it will definitely be answerable to the democratically-elected House. Therefore, I personally would not be afraid that the powers that are sought to be taken under this Act could be misused by any democratic Government. If the democracy itself goes off from this nation, from this country, that is another matter. Then, there can be all kinds of misuse of authority. But if there is a democracy, if the nature of the party which is running the Government is different, then also there need not be any misapprehension because whatever is done will be brought forward in the elected from of the State Assemblies or in this honourable House or the Parliament. Then, the representatives of the people could have their say in the matter and the Government will be completely exposed. The greatest deterrent to any wrong use of the measure is the strong public opinion. So, any Government which misuses any provision will definitely be condemned by the public opinion.

I will not try to soften down the Bill or the provisions which we want to incorporate in this Bill only on the imaginary fear that the provision may be misused in future by a Government which will not be democratically inclined.

I am grateful to Mr. N. K. Somani for having given some valuable suggestions during his intervention. Here, I want to say that this Bill is definitely permitting or suggesting certain negative measures, that is to

ہیں۔ یہ سب اچھا ہے۔ ان لوگوں کو ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کو کوئی حریف ہو، ان کو ان کے لئے مناسب ہے۔

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :
Mr. Chairman, Sir, I am thankful to hon. Members for lending their support to this measure. However, certain Members have expressed their reservations on a few things and I would do my best to clarify them.

First of all, I want to clarify that this is not a complete measure. As a matter of fact, there are already certain powers available to the Government which are enough to deal with situations which are created by those forces which encourage communalism, regionalism or factionalism or other fissiparous tendencies in our society and community life. But wherever we found there was any gap, wherever we found there was any difficulty, there we have sought to amend those laws and bring them forward to the aim that was prescribed by the National Integration Council. Here, we have also amended the Election law, to make a provision in it that anybody who is convicted by a court of law under any of these offences inciting communal feelings or regional feelings or factional feelings which seek to destroy our

say, certain measures to control certain unhealthy tendencies.

As far as positive measures are concerned, positive action is being taken by the National Integration Council, and the Home Ministry which is in charge of national integration matters is taking positive action by organizing seminars and helping people to hold gatherings in which the idea of national integration is promoted. It is being done in a completely non-political manner. So far, we have organized several things like that. I do not think that anybody has so far alleged any political motivation in such matters. The people having national reputation, people whose integrity is completely above doubt, those who are not motivated by party considerations, have been encouraged to make their contributions and such positive measures have created a healthy tendency. We are determined to carry forward this programme of positive encouragement to healthy tendencies in the society so that it does not become necessary to use the provisions of this law. We would be very happy if the provisions of this law are not required to be used by the authorities. This is only a preventive measure and a measure to nip in the bud any mischief which may be sought to be created.

Mr. Abdul Ghani Dar and another hon. Member were apprehensive that action under the law had been taken only against Muslim papers...

SHRI ABDUL GHANI DHAR : I never said that.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : ...against Urdu papers.

SHRI ABDUL GHANI DHAR : Yes. Action was taken against so many Urdu papers.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I would say that we have gone into each and every case because this matter was raised even earlier in this House and we wanted to find out whether there was any mistake or whether there were any untoward feelings or wrong feelings because of which only certain language newspapers were prosecuted and the others were not prosecuted. We have found that in each case there was sufficient material to take action. It may be that, in certain other cases, action was not taken. I am not saying

that action was taken in every case, but there was no *mala fide* in taking action; there was no intention on the part of anybody to proceed against only one type of language newspapers and leave off the others. Here the question is that, whenever any such tendency or any such writings which seek to inflame communal bias and feelings comes to our notice, action has to be taken. If in certain cases action has not been taken and action should have been taken, I would be grateful to the hon. members if such instances can be brought to our notice and we will certainly see that, in future, no such lapse occurs. I am not saying that no lapse has occurred. In case any lapse has occurred, I would be grateful if the hon. members could bring it to our notice so that the lapse could be corrected in future. As far as I can see, I have not been able to find out a case in which action should have been taken and where action has not been taken. I would reassure the hon. members and particularly Shri Abdul Ghani Dhar, that no action was taken on a newspaper because it was printed in a certain language. It may be a coincidence that a large number of cases were initiated in one particular group but that is not because of any intention or ill-will; it may be just accidental that it happened so.

AN HON. MEMBER : What about *Organizer* ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as I can remember, action has been taken against *Organizer* also; it is not that *Organizer* has been spared in this matter.

My hon. friend, Mr. Om Prakash Tyagi, was pleased to say that the main malady or the main difficulty lay with the political leaders. The reply to it was given by Mr. Viswanathan who expressed the view that political leaders might be proceeded under the Act, under the powers which are sought to be taken under this Bill. One member of the Opposition says that action should be taken against leaders and another Opposition member says that he is afraid that action is going to be taken against leaders. If the leaders behave in an irresponsible manner and promote communal disharmony and regional feelings which create difficulty or communal tension and rioting or any kind of violent activities, then action would be taken against

[Shri Vidya Charan Shukla]

leaders also irrespective of the parties to which they belong.

The leaders would not be immune from such things. I agree with the hon. Member, Shri Tyagi, that if the leaders were to behave in a proper and responsible manner, most of our difficulties will be over. If the leaders belonging to all Parties either at the top or the middle or the lowest rung of the ladder behave in a proper and responsible manner, most of our troubles in this respect will be over. It is not as if leaders will be excluded. Anybody who commits an offence under this Act would be proceeded against and no exception will be made against leaders of political opinion if they seek to misuse the the places of religious worship, etc. Here again, Shri Tyagi expressed his doubt which we expressed earlier at the first reading as also during the second reading that in places of religious worship if a particular method of religious worship is propagated it is bound to hurt the feelings of others who are following that particular mode of worship. I beg to disagree from that. The religious propagation or a particular mode of religious worship can be propagated, can be explained by the religious preacher without hurting the feelings of others.

श्री श्रीमन्नकाश स्वामी : एक प्रोपेगेशन है और एक मोड आफ वरशिप है। मोड आफ वरशिप कहाँ घटक करना है ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :

If it does not hurt the feelings of others, the provisions of this Bill will not come into play. This is only a preventive measure. In case anything is done which hurts the religious feelings of other the provisions of this Bill will come into operation.

One of the hon. Members also asked as to why only the places of religious worship should be selected. Other places are also there. This Bill embraces all the places. Wherever this can be done, wherever this offence is committed, the offence can be punished. We have made only an additional provision. If the offence is committed in a place of religious worship, then there would be enhanced punishment. It is not as if other places are excluded. If this kind of offence is committed in any place, it is

actionable under this particular Bill. But, if it is committed in a place of religious worship, then it becomes an aggravated offence and, therefore, enhanced punishment have been prescribed.

Shri Viswanathan also mentioned that Government have already too many powers and they are not able to use them. I would like to submit to him that we carefully went into this matter and we tried to find out if the recommendations made by the National Integration Council can be covered by the powers that are already available to the State Governments or to the Central Government and whether we could fulfil our obligations if we accepted the recommendations of the National Integration Council without amending any Act and after that examination we found that in this particular respect in which this Bill has been drafted we were lacking power. That is why this power is sought to be taken under this amending Bill and, therefore, it is not proper to say that we are taking powers without having any need for them. These powers are not being taken by the Central Government for themselves. They are being made available to the State Governments because it would be primarily for the State Government to take action in such matters to see that no such ill-will and such inflammatory situation is created in the State because the people who are directly in charge of the State Governments are the greatest sufferers as far as this particular matter is concerned.

Here I would end my reply by saying one thing. The main object of this Bill is to completely curb the tendency which seeks to destroy our national life and our community life and our national unity. There is no other purpose behind this Bill and I am sure the hon. Members have realised this aim behind this Bill. Therefore, practically every hon. Member has supported this measure and I can only assure them that as far as Government is concerned, the provisions of this Bill and the powers taken under this Act would be used with the greatest circumspection and there would be no prosecution or *mala fide* use of the powers under this Bill and, therefore, no political party need entertain any apprehension as far as the powers of this Bill are concerned.

Having said this, I would commend this Bill to the acceptance of this House.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill, *as amended*, be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The Bill is passed. Now we go to the next item—Delhi High Court (Amendment) Bill.

15.46 hrs.

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, on behalf of Shri Vidya Charan Shukla, I move that the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, be taken into consideration.

Sir, under Section 5 (2) of the Delhi High Court Act, 1966, the Delhi High Court has ordinary original civil jurisdiction in every suit, the value of which exceeds Rs. 25,000/-. Under Section 17 (3) of the same Act, the High Court has such original jurisdiction in respect of the Union Territory of Himachal Pradesh also. After the establishment of the High court, it was found that the limit of Rs. 25,000/- for civil suits was too low and large number of cases were filed in the High Court and the High Court started accumulating arrears. So it was thought necessary that the limit of Rs. 20,000 should be raised to Rs. 50,000 and the High Court should have ordinary original civil jurisdiction of suits, the value of which exceed Rs. 50,000/-. Consequent to this, the arbitration jurisdiction of the High Court will also, under the Arbitration Act, be corresponding raised to suit whose value exceeds Rs. 50,000/-.

Article 112 (3) relating to expenditure charged on the Consolidated Fund of India does not provide for salaries and allowances of Judges of the High Court for a Union Territory and the necessary provision has to be made by Parliament by law and this opportunity is taken to provide for a provision in the Delhi High Court Act to the effect that expenditure in respect of

salaries and allowances of Judges of the Delhi High Court shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of India on the lines of the corresponding provision applicable to State High Courts in Article 202 (3) (d) of the Constitution.

The Bill seeks to achieve these objects, and I believe that the House will concur with it.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, be taken into consideration."

Mr. Pandey is absent. Amendment No. 15 by Shri Mandal and Amendment No. 17 by Shri O. P. Tyagi may be moved.

SHRI B. P. MANDAL (Madhipura) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th November, 1969." (15)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th October, 1969." (17)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, the delay which has been caused in the matter of disposal of cases has made it necessary for the Government to upgrade the jurisdiction of the Delhi High Court. Delay of the law is considered a negation of the law. In fact, recently, a High Court Judge is on record to say that the delays which are occurring in our High Courts are likely to lead to a complete collapse of justice. I would like to give some statistics to which I wish to draw the attention of the Hon. Minister.

In 1965, there were 2.163 lakhs of cases pending of which 88,000 were more than 2 years old. In 1968, the number has increased to 3.34 lakhs of which 1.12 lakhs are more than 2 years old. The statistics for Delhi are in the same scale. The pendency when the Delhi High Court was constituted was 6,600. The pendency now is 18,000.

15.50 hrs.

[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

These figure imply that our High Courts